वहन के सुरक्षा संबंधी उपाय करें और उन्हें कार्यान्वित करें।

(v) यातायात के प्रवाह, यातायात संघटन, सड़क दुर्घटनाओं आदि को दर्शाने के लिए एक डेटा-बेस विकसित करने की दृष्टि से, जो अंततः सड़क परिवहन के विकास के लिए नीति-निर्धारण में सहायता करता है, राष्ट्रीय रोड ब्रेकिंग संस्थान स्थापित किया जा रहा है।

5. अन्तर्देशीय जल परिवहन

(i) सातवीं योजना अवधि के दौरान अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए सातवीं योजना (केन्द्रीय क्षेत्र) में 155.73 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। नए जहाज खरीदने और सी०आई० डब्लू टी०सी० के राजाबागान डाकयार्ड के आधुनिकीकरण के लिए महत्वपूर्ण जलमार्गों के जलीय सर्वेक्षण, सर्वेक्षण लांचों और उपस्करों की खरीद, राष्ट्रीय जल मार्गों का अनुरक्षण, तटवर्ती सुविधाएं स्थापित करने और नौचालन उपकरणों आदि के लिए पूंजी लगाई जा रही है/पूंजी लगाई जानी है।

(ii) जहां तक अंतर्देशीय नौचालन का सम्बंध है राष्ट्रीय जल मार्गों के रखरखाव प्रबंध और संचालन के लिए भारतीय अन्तर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण स्थापित करने के लिए कार्यवाई शुरू कर दी गई है।

(iii) गंगा-भगीरथी-हुगली रिवर सिस्टम पर जलमार्ग संख्या 1 का चरणबद्ध विकास कार्य शुरू किया गया है।

(ख) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम गंगा पर कलकत्ता और फरक्का के बीच नियमित नदी सेवाएं पहले से ही चला रहा है। फरक्का नौचालन लाक स्थापित हो जाने के बाद निगम की नदी सेवाओं का फरक्का अपस्ट्रीम से पटना इलाहाबाद तक चरणबद्ध ढंग से विस्तार किया जाएगा।

(ग) मुंगेर में गंगा नदी पर रेलवे पुल अथवा रेल व सड़क पुल बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

Suspension of Clerks at Ariyalur Southern Railway

2027. SHRI ALADI ARUNA *alias* V. ARUNACHALAM: Will the Minister of TRANSPORT be pleased to state:

(a) the number of tally clerks of the Southern Railway at Ariyalur who have been suspended during the last three years for having allowed the State Government owned cement factory to accumulate huge arrears in freight charges payable to the railways; and

(b) whether Government have instituted any enquiry into the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RAILWAYS (SHRI MADHAVRAO SCINDIA): (a) Four Tally Clerks were suspended at Ariyalur, Southern Railway on 1-5-86 and were subsequently put back to duty on 28-6-86.

(b) Fact finding inquiry was conducted and disciplinary action against the staff found errant by the Fact Finding Inquiry Committee is being processed.

लक्ष्मी नगर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की डिस्पेंसरी की आवश्यकता

2028. **श्री राम नरेश कुशवाहा:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी०जी०एच० एस०) ने यमुना पार क्षेत्र के मयूर विहार में केवल डेढ़ हजार कार्डधारियों के लिए आपातकालीन सेवाएं आरम्भ कर दी है, जबकि लक्ष्मी नगर और शकरपुर में सात हजार कार्डधारी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि मयूर विहार में केवल एक ही डिस्पेंसरी है और इस तक आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों की सुविधा के लिए लक्ष्मी नगर या गीता कालोनी में डिस्पेंसरी खोलने का विचार रखती ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या करण है;

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे): (क) मयूर विहार स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय को फंक्शनिग औषधालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, क्योंकि यह काफी दूर दराज के क्षेत्र में स्थित है। वैसे इस औषधालय में दर्ज कार्डधारियों की संख्या 2262 है।

(ख) वर्तमान औषधालय में आसानी से पहुंचा जा सकता है।

(ग) और (घ) जी नहीं। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय पहले ही इन कालोनियों में कार्य कर रहे है।

Dubbing of films into other languages

2029. SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government had directed that when a motion film already certified for public exhibiton is dubbed in another language, the 'visual side' should remain uncensored and only the audio portion could be censored, in case of any objection thereto;

(b) if so, when was such an order rescinded and what were the reasons therefor; and

(c) what steps Government have taken to encourage the dubbing of good films into various other Indian languages to promote and strengthen national integration?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION AND CULTURE (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) and (b) In order that uniform standards are applied while examining films dubbed in various languages, it was decided that there should be no censorship of the visuals in the case of dubbed films, provided the Central Board of film Certification was satisfied that visuals of the dubbed version were exactly the same as the visuals of the original certified version. It was decided that the Board should examine the dubbed films in the light of that decision. However, in the recent past, the Central Board of Film Certification has been facing problems with regard to certification of dubbed versions of certified films. The Board has also found that some cases of dubbed versions are not the same as the original certified films. The Board has been treating dubbed versions which are not exact copies of the original versions as fresh films and are examining them as such.

(c) Cinema (excluding certification of films for public exhibition) is a State subject and production of films is mainly in the private sector. However, the Ministry of Information and Broadcasting have time and again recommended to the State Governments that national award winning films and their dubbed versions should be exempted from payment of entertainment tax. Besides, the National Film Development Corporation, a public sector undertaking under the Ministry of Information and Broadcasting gives loans to producers for *interalia* dubbing of films in various Indian languages.

Control over quality of disposable syringes

2030. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have issued instructions to all Government hospitals, blood banks, health care units, etc. to use only disposable syringes and needles to prevent transmission of AIDS;